RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 13 OCTOBER TO 19 OCTOBER 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 7 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

लगातार पांचवें दिन बाजार में तेजी सेंसेक्स 453 अंकों की उछाल के साथ रिकॉर्ड .. Page 2

डी.पी. ज्वैलर्स ने इंदौर में अपने स्टोर में डी बीयर्स कोड ऑफ ओरिजिन लॉन्च किया Page 3

मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स में जागरूकता के लिये थ्री-आर थीम पर गरबा आयोजित Page 5

editoria!

वैश्विक कर प्रणाली

पूंजी, श्रम व तकनीक के विस्तार के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गयी है. एक से अधिक देशों में अपने उद्योग, सेवा और उत्पादन तंत्र से इन कंपनियों की भारी आमदनी होती है, लेकिन उस हिसाब से कई देशों को राजस्व नहीं मिल पाता है. ये कंपनियां या तो उस देश को कर देती हैं, जहां उनके मुख्यालय होते हैं या वे ऐसे देशों में अपने कार्यालय खोलती हैं, जहां उन्हें कम कर चुकाना पड़ता है. इस वजह से उन देशों को भी राजस्व का नुकसान होता है, जो वास्तव में आय में मुख्य योगदान करते हैं. इस विसंगति को दूर करने के लिए इस वर्ष जुलाई में 130 देशों ने वैश्विक न्यूनतम कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है. भारत भी इन देशों में शामिल है और वह इस प्रणाली के प्रारूप पर अपनी राय को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. इसमें प्रावधान किया गया है कि कंपनी जिस देश में कार्यरत होगी, वहां उसे कम-से-कम 15 प्रतिशत कर देना होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जतायी है कि जल्दी ही सभी देश इस संबंध में निर्णय कर लेंगे. अगले सप्ताह अमेरिकी राजधानी में जी-20 देशों के वित्तमंत्रियों की बैठक संभावित है. भारत उन देशों में शामिल है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा समुचित कर न देने की प्रवृत्ति के शिकार हैं. कई ऐसी कंपनियां हैं, जो यह तर्क देती हैं कि उनका मुख्यालय अन्यत्र है, इसलिए वे कुछ करों को यहां नहीं भरेंगे. मौजूदा व्यवस्था में ठोस कानूनी प्रावधानों की कमी और ताकतवर देशों के दबाव की वजह से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को राजस्व घाटे के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ता है. डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के प्रसार ने भी सरकारों को लाचार कर दिया है. हालांकि ऐसी कर व्यवस्था की मांग अविकसित और विकासशील देश लंबे समय से कर रहे थे, पर धनी देश अपनी कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे थे. विभिन्न देशों के कानूनों में भिन्नता तथा अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर कंपनियों ने जब विकसित देशों में ही कम कर देना शुरू किया, तब उनकी नींद खुली. इसका परिणाम वैश्विक कराधान के रूप में हमारे सामने है. इसके लागू हो जाने के बाद अगर कोई कंपनी भारत में अपनी गतिविधियों से जो अर्जित करेगी, उस हिसाब से उसे निर्धारित कर देना होगा. अनेक तकनीकी कंपनियां ऐसी हैं, जिनकी उपस्थिति बड़े उद्योगों की तरह नहीं है, पर वे भारत जैसे देशों से खूब कमाती हैं. कुछ साल से भारत सरकार और तकनीकी कंपनियों में इस मसले पर तनातनी भी है. भारत और चीन समेत 130 से अधिक देशों ने इस व्यवस्था का समर्थन किया है, पर सफलता के लिए अधिकतर देशों की अंतिम सहमति अनिवार्य है, अन्यथा बड़ी कंपनियां कर बचाने के रास्ते निकाल लेंगी. भारत को इस प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभानी है क्योंकि तकनीकी कंपनियों का बड़ा बाजार हमारे देश में है.

मोदी सरकार बढ़ा सकती है GST

चार रेट वाले सिस्टम में हो सकता है बदलाव

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार कुछ सामान और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम पर ज्यादा सरल टैक्स रेट स्ट्रक्चर करने के मकसद के साथ विचार किया जा रहा है। बता दें जीएसटी दरों को बढ़ाने की यह योजना ऐसा समय पर की जा रही है, जब अगले साल की शुरुआत में देश के बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं।

जीएसटी की वर्तमान दरें

जीएसटी पर पैनल की बैठक दिसंबर में होने की उम्मीद है। इस पैनल की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इसमें वर्तमान के चार रेट वाले सिस्टम से बदलाव किया जा सकता है। इस समय देश में 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है। इसमें कुछ जरूरी सामान जैसे खाने की चीजों पर सबसे कम दर और लग्जरी सामान पर सबसे ज्यादा रेट से टैक्स लगता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया है कि अगली बार सबसे कम दो रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है।

तो आम आदमी ही पिसेगा

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम दो दरों में से एक 5 फीसद को बढ़ाकर 6 फीसद और 12 को 13 फीसदी किया जा सकता है। इन दो दरों से सबसे ज्यादा प्रभावित आम आदमी ही होता है। इस चरणबद्ध योजना के तहत दरों को चार से घटाकर तीन पर लाया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री अगले महीने के आखिर तक इस मामले में अपने प्रस्तावों को रख सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने वित्त मंत्रालय को इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया, लेकिन वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें जुलाई 2017 से मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी की एक देश, एक टैक्स व्यवस्था के तहत आपको एक ही टैक्स देना होता है। जीएसटी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसी भी सामान या सर्विस पर इस टैक्स की दर पूरे देश में एक जैसी होती है। यानी देश के किसी हिस्से में मौजूद कस्टमर या कंज्यूमर को उस वस्तु या सेवा पर एक जैसा ही टैक्स देना होता है. जीएसटी को 3 प्रकार में बांटा गया है— सेंट्रल जीएसटी (CGST), स्टेट जीएसटी (SGST) और इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल मिशन अमृत 2.0 को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन - अमृत 2.0 को 2025-26 तक के लिए मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । सरकारी बयान के अनुसार, अटल मिशन (अमृत 2.0) का मकसद आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था के जरिए शहरों को जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें कहा गया है कि अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है तथा इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।बयान के अनुसार, परियोजनाओं के लिए धन केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा साझा किया जाएगा। राज्यों को केंद्रीय निधि राज्य जल कार्य योजना के अनुसार राज्य के आवंटन के आधार पर तीन चरणों में जारी की जाएगी। मिशन का लक्ष्य सभी 4,378 सांविधिक कस्बों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज हासिल करना है । बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल का मानना है कि शहरी परिवारों को विश्वसनीय और सस्ती जलापूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसके तहत सभी घरों को चालू नल कनेक्शन प्रदान करके, जल स्रोत संरक्षण/वृद्धि, जल निकायों और कुंओं का कायाकल्प, शोधित किए गए पानी का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग और वर्षा जल संचयन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। मिशन के तहत 500 अमृत शहरों में घरेलू जलमल निकासी एवं प्रबंधन का 100 प्रतिशत कवरेज लक्षित किया गया है। इसका लक्ष्य 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करना है। गौरतलब है कि नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जून 2015 में 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था।

कमजोर हाजिर मांग के कारण कच्चा तेल वायदा कीमतों में गिरावट

नयी दिल्ली। एजेंसी

कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चे तेल की कीमत 22 रुपये की हानि के साथ 6,072 रुपये प्रति बैरल रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल के अक्टूबर माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 22 रुपये अथवा 0.36 प्रतिशत की हानि के साथ 6,072 रुपये प्रति बैरल रह गई जिसमें 7,824 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के कारण व्यापारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से वायदा कारोबार में कच्चा तेल कीमतों में गिरावट आई। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टैक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का दाम 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80.51 डालर प्रति बैरल रह गया। इस बीच वैश्विक मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड का दाम 0.13 प्रतिशत घटकर 83.31 डालर प्रति बैरल रह गया।

News यू केन USE

देश में सीमेंट उत्पादन पिछले पांच माह में 44 प्रतिशत बढ़कर 14.2 करोड़ टन पर : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। देश में सीमेंट उत्पादन पिछले पांच महीनों के दौरान सालाना आधार पर 44 प्रतिशत बढ़कर 14.2 करोड़ टन पर पहुंच गया। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-सितंबर, 2021 के दौरान सीमेंट उत्पादन में कोविड-पूर्व की अप्रैल-सितंबर, 2019 अवधि की तुलना में दो प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इक्रा ने उम्मीद जताई है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरे भारत में सीमेंट उत्पादन 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 33.2 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा। अगले वित्त वर्ष 2022-23 में यह 35.8 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। इक्रा ने सीमेंट उद्योग पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि दबी मांग, ग्रामीण आवास की मांग और बुनियादी ढांचे की गतिविधियों में तेजी से सीमेंट उत्पादन को बल मिलेगा। वही वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीमेंट उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़कर 35.8 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी पाया कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सालाना आधार पर सीमेंट की कीमतों में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डाक विभाग ने डाक जीवन बीमा पॉलिसी का डिजिटल संस्करण जारी किया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

डाक विभाग ने मंगलवार को डाक जीवन बीमा पॉलिसी -ईपीएलआई बांड का डिजिटल संस्करण जारी किया। अब अंशधारकों की पहुंच डिजिलॉकर के जरिये इस पॉलिसी तक होगी। डॉक विभाग ने कहा कि डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) पॉलिसी बांड अब 'इलेक्ट्रॉनिक रूप' में उपलब्ध होंगे। सभी लेनदेन के लिए इसकी डिजिटल प्रति को वैध दस्तावेज माना जाएगा। डॉक विभाग के सचिव विनीत पांडेय ने ईपीएलआई बांड की शुरुआत करते हुए कहा कि यह विभाग का डिजिलॉकर के साथ पहला एकीकरण है। ईपीएलआई बांड डिजिलॉकर के साथ सहयोग में उपलब्ध होगा। इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी (मेइटी) मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-संचालन प्रभाग ने किया है।

जीवनरक्षक दवाओं की मांग में उछाल के साथ इंदौर सेज से 12.25 प्रतिशत बढ़ा निर्यात

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जीवनरक्षक दवाओं की मांग में उछाल से मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से सितंबर के दौरान इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) से निर्यात करीब 12.25 प्रतिशत वृद्धि के साथ लगभग 6,359 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इस बहुउत्पादीय सेज से 5,665 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया,'इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच इंदौर सेज से हुए निर्यात में करीब 60 फीसद भागीदारी दवाओं, खासकर जीवनरक्षक औषधियों की रही।' उन्होंने बताया कि फिलहाल इंदौर सेज में फार्मा, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग, वस्त्र निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण समेत अलग-अलग क्षेत्रों के 60 संयंत्र चल रहे हैं। इनमें से 20 इकाइयां अकेले फार्मा क्षेत्र की हैं। यह सेज हालांकि इंदौर के पास धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में स्थित है। लेकिन 1,100 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैली इस जगह को आधिकारिक तौर पर 'इंदौर सेज' के नाम से ही जाना जाता है।

लगातार पांचवें दिन बाजार में तेजी

सेंसेक्स 453 अंकों की उछाल के साथ रिकॉर्ड 60737 अंक पर बंद, निफ्टी 18100 के पार

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

आईटी, ऑटो, मेटल और इंफ्रा कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बुधवार को घरेलू शेयर नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 452.74 अंकों की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 60,737.05 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 60,836.63 के ऑलटाइम हाई पर गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 169.80 अंक यानी 0.94 प्रतिशत के उछाल के साथ 18,161.80 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी का भी यह नया रिकॉर्ड है। बाजार में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स

की कंपनियों में एमएंडएम का शेयर सबसे अधिक 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया। पावरग्रिड, आईटीसी, एलएंडटी, टाइटन, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, सनफार्मा के शेयरों में भी बढ़त रही। बाजार में तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 271 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया।

5 दिन में निवेशकों की दौलत 8.96 लाख करोड़ बढ़ी

बाजार में तेज से निवेशकों की दौलत में भी पांच दिनों में 8,96,772.97 करोड़ रुपये का उछाल आया है। हाल के दिनों में बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति एफआईआई और डीआईआई दोनों द्वारा बिक्री के बावजूद बाजार में मजबूती है। यह नया चलन खुदरा निवेशकों के प्रभुत्व को मजबूत करता है और गिरावट में खरीदारी की रणनीति की सफलता है।

BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 270 लाख करोड़ के पार

लगातार पांच दिनों से घरेलू शेयर बाजार में जारी तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बुधवार के कारोबार में 270 लाख करोड़ रुपये के पार कर गया। कारोबार के दौरान बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2,71,18,390.15 करोड़ के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। बुधवार को लगातार पांचवें सत्र में रैली के चलते 30 शेयर बीएसई बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 60836.63 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

सरकार एथनॉल उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है: गडकरी

नयी दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एथनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त चीनी स्टॉक के स्थानांतरण की जरूरत पर जोर दिया। इसकी वजह यह है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की व्यवस्था के तहत दिसंबर, 2023 के बाद से चीनी के निर्यात पर सब्सिडी का प्रावधान नहीं होगा।

उद्योग मंडल इस्मा द्वारा आयोजित वैकल्पिक ईंधन पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार एथनॉल विनिर्माण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह देश में उत्पादित सभी एथनॉल की खरीद करेगी। एथनॉल की आपूर्ति में वृद्धि के साथ, गडकरी ने कहा कि सरकार देश में फ्लेक्स-ईंधन इंजन वाले वाहनों को पेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत बायो-एथनॉल पर फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की पेशकश के साथ एथनॉल की मांग तुरंत 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। मंत्री ने चीनी मिलों को अपने स्वयं के एथनॉल पंप स्थापित करने के लिए भी कहा, जिन्हें सरकार द्वारा अनुमति दी जा रही है। गडकरी ने कहा कि सरकार चीनी मिलों को अधिशेष चीनी स्टॉक को समाप्त करने के लिए 3,000 से 6,000 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी प्रदान कर रही है।उन्होंने कहा, "डब्ल्यूटीओ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं के कारण, ये सब्सिडी दिसंबर, 2023 के बाद स्वीकार्य नहीं होगी।" इस समस्या के समाधान के रूप में, गडकरी ने सुझाव दिया कि बी-हेवी मोलासेस में 15-20 प्रतिशत चीनी मिलाकर अतिरिक्त चीनी स्टॉक को एथनॉल उत्पादन की ओर मोड़ा जा सकता है। पेट्रोलियम ईंधन के साथ 20 प्रतिशत एथनॉल के मिश्रण का स्तर प्राप्त करने के लिए देश को वर्ष 2025 तक लगभग 10 अरब लीटर एथनॉल की आवश्यकता होगी। मौजूदा समय में, चीनी उद्योग देश में मिश्रिण किये जाने वाले ईंधन के रूप में एथनॉल की 90 प्रतिशत मांग को पूरा करने में अपना योगदान देता है। उपलब्ध संसाधनों के साथ एथनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए गडकरी ने बी-हेवी मोलासेस में 15-20 प्रतिशत चीनी मिलाने का सुझाव दिया।

शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे चढ़कर 75.26 पर पहुंचा

मुंबई। एजेंसी

सकारात्मक वृहद आर्थिक आंकड़े और घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के साथ बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे चढ़कर 75.26 पर पहुंच गया। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत कम गिरने और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा में नरमी से भी रुपये को मदद मिली। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूती के साथ 75.29 पर खुला, फिर और चढ़कर 75.26 पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 26 पैसे की बढ़त को दिखाता है। शुरुआती सौदों में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 75.25 की ऊंचाई पर भी पहुंच गया था। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे टूटकर 75.52 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.18 प्रतिशत गिरकर 94.35 पर था। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83.29 डॉलर प्रति बैरल हो गया। विदेशी संस्थागत निवेशक मंगलवार को पूंजी बाजार में शुद्ध विक्रेता थे और शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 278.32 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर, 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 302.33 अंक या 0.50 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,586.64 पर कारोबार कर रहा था, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 114.75 अंक या 0.64 प्रतिशत बढ़कर 18,106.70 पर पहुंच गया।

सरकार बिजली उत्पादों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करने का प्रयास कर रही है: जोशी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि सरकार बिजली उत्पादकों (जेनको) की कोयले की मांग को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोयला आपूर्ति अभी 19.5 लाख टन प्रतिदिन की है जिसे बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन करने का प्रयास किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा, "कोयला मंत्रालय में हम इस ईंधन की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को आपूर्ति 19.5 लाख टन रही है। इसमें से 16 लाख टन कोयला कोल इंडिया ने तथा शेष सिंगरेली कोलियरीज कंपनी ने भेजा। कुल मिलाकर 19.5 लाख टन की आपूर्ति की गई।' कोयला मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि देश के बिजली संयंत्र कोयला संकट से जूझ रहे हैं। जोशी ने कहा, "मुझे लगता है कि यह देश के इतिहास में सबसे अधिक आपूर्ति है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह जारी रहेगी।" जोशी ने कोयले के वाणिज्यिक खनन की तीसरे चरण की नीलामी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, "2020-21 अक्टूबर या उससे पहले हम 20 लाख टन की आपूर्ति पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। यह भी एक रिकॉर्ड होगा।" मंत्री ने सभी हितधारकों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, "मैं सभी हितधारकों तथा देश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि बिजली उत्पादन के लिए जितने भी कोयले की जरूरत होगी कोयला मंत्रालय उसे उपलब्ध कराएगा।" उन्होंने कहा कि मानसून लौटने के साथ अब कोयला आपूर्ति और सुधरेगी।

जोशी ने कहा, "अभी कोल इंडिया के पास 22 दिन का भंडार है। आप जानते हैं कि मानसून लौट रहा है। ऐसे में आपूर्ति और सुधरेगी।" मंत्री ने कहा कि अगले 30-40 साल निश्चित रूप से कोयले का भविष्य है। उन्होंने कहा कि यह कोयला ब्लॉकों की तीसरे चरण की नीलामी के लिए उपयुक्त समय है। पूरी दुनिया और भारत के कुछ हिस्सों में कोयले के भविष्य को लेकर चर्चा चल रही है। कोयला सचिव ए के जैन ने भी कहा कि यह कोयले के वाणिज्यिक खनन के लिए तीसरे चरण की नीलामी को उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय कोयले की आपूर्ति को लेकर चर्चा चल रही है। "साथ ही कोयले की मांग भी है।"

डी.पी. ज्वैलर्स ने इंदौर में अपने स्टोर में डी बीयर्स कोड ऑफ ओरिजिन लॉन्च किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

आने वाले समय के उपभोक्ता बदल रहे हैं और सामाजिक एंव पर्यावरणीय रूप से सचेत उपभोक्ताओं की एक नई पीढी उभर रही है। ये उपभोक्ता ऐसे उत्पादों और ब्रांड्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनके सुदृढ वैल्यू लोगों से जुड़े हों और पर्यावरण को बेहतर बनाते हों। ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, डी बीयर्स ने डी.पी. ज्वैलर्स में अपना विश्वसनीय डायमंड प्रोग्राम कोड ऑफ ओरिजिन लॉन्च किया, जो सुंदर और दुर्लभ डायमंड से बेहतरीन ज्वैलरी बनाते हैं।

डी बीयर्स कोड ऑफ ओरिजिन एक भरोसेमंद सोर्स प्रोग्राम है जो सामाजिक एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति डी बीयर्स की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे उपभोक्ता को इस बात पर गर्व हो सकता है कि उसके पास जो डायमंड हैं, वे डी बीयर्स से लिए गए हैं। डी बीयर्स कोड ऑफ ओरिजिन इस बात का प्रमाण है कि डायमंड प्राकृतिक और कॉन्फलिक्ट-फ्री हैं और वे डायमंड बोत्सवाना, कनाडा, नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका में डी बीयर्स द्वारा खोजे गए थे, जहां डी बीयर्स ने रोजगार, शिक्षा, हेल्थकेयर और वन्यजीव संरक्षण प्रदान करने में मदद की है। ज्वैलरी के प्रत्येक पीस के साथ 12 अंकों का कोड होता है जिसकी शुरुआत डीबीएम अक्षरों से होती है। इस कोड को प्रत्येक ज्वैलरी के साथ मौजूद डी बीयर्स कोड ऑफ ओरिजिन कार्ड पर भी देखा जा सकता है। यह कोड खरीदारों को यह गारंटी भी देता है कि उनकी ज्वैलरी में लगे डायमंड 100ङ्ग प्राकृतिक, ट्रेस करने योग्य, सस्टेनेबल तरीके हासिल किए गए हैं।

श्री विकास कटारिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, डी.पी. ज्वैलर्स ने कहा कि 'डी बीयर्स जैसे ब्रांड के साथ जुड़कर और इंदौर में अपने स्टोर पर कोड ऑफ ओरिजिन' प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। नैतिक और टिकाऊ प्रथाओं की गारंटी के साथ 0.08 कैरेट और उससे कम की प्रामाणिक नेचुरल ज्वैलरी की पेशकश हमारे उपभोक्ताओं के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। ' श्री अनिल कटारिया, प्रमोटर, डी.पी. ज्वैलर्स ने कहा कि 'एक ब्रांड के रूप में हम सर्वोत्तम ऑफर देने का प्रयास करते हैं जो

हमारे वैल्यू को मजबूती प्रदान करते हैं और हमारे ग्राहकों को लाभ पहुंचाते हैं। हम डी बीयर्स के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को लेकर आशान्वित हैं।'

डी बीयर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सचिन जैन ने कहा कि 'डी बीयर्स ब्रांड अपने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कोड ऑफ ओरिजिन प्रोग्राम लाया है जो हमारे विश्वसनीय रिटेलर पार्टनर्स के जरिये उनकी डायमंड ज्वैलरी के स्रोत और यात्रा के बारे में पूरी पारदर्शिता प्रदान करता है। डी बीयर्स कोड ऑफ ओरिजिन गारंटी हमारे उपभोक्ताओं को न केवल डी बीयर्स डायमंड के मालिक होने और पहनने को लेकर अच्छा अहसास देगी, बल्कि यह आश्वासन भी देगी कि वे डायमंड कार्बन न्यूट्रल के लिए प्रतिबद्ध कंपनी से लिये गए हैं, जो कंपनी अपने 2030 बिल्डिंग फॉरएवर लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। डी बीयर्स कोड ऑफ ओरिजिन इंस्क्रिप्शन के साथ एक ज्वैलरी पीस खरीदकर, उपभोक्ता स्वयं हमारे 2030 बिल्डिंग फॉरएवर मिशन में योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना जा सके।' डी बीयर्स कोड ऑफ ओरिजिन, बेहतर भविष्य के लिए अपनाये गए ब्रांड के बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसे फलते फूलते समुदायों के लिए साझेदारी करते हुए, प्राकृतिक दुनिया का संरक्षण करते हुए, और समान अवसर में तेजी लाते हुए इंडस्ट्री में अग्रणी नैतिक प्रथाओं के आधार पर 12 स्थायी लक्ष्यों के जरिये तैयार किया गया है।

डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया ने दिए त्यौहारों के लिये खास ऑफर्स

डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया सभी इंटरनेशनल शिपमेंट्स पर 40% छूट की पेशकश

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

डीएचएल एक्सप्रेस, विश्व का अग्रणी अंतराष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवा प्रदाता है, त्यौहारों के इस मौसम में ग्राहकों के लिये सभी इंटरनेशनल शिपमेंट्स पर 40ङ्ग छूट की पेशकश कर रहा है। ग्राहक अब दिवाली के आनंदमय अवसर को यादगार बनाने के लिये विदेशों में रह रहे अपने प्रियजनों को फेस्टिव हैम्पहर्स, मिठाइयाँ और तोहफे भेज सकते हैं। यह छूट 2 किलो से 10 किलो, 15 किलो और 20 किलो के शिपमेंट्स पर लागू है और 11 अक्टूरबर से 6 नवंबर 2021 तक वैध रहेगी। यह ऑफर लेने के लिये ग्राहक या तो 8422930000 पर एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं या डीएचएल को 56161 पर ऑफर कोड ईऐंऊर्ध्ंथ का इस्तेपमाल कर एसएमएस कर सकते हैं। यह ऑफर भारत में डीएचएल एक्स प्रेस के सभी 650 सर्विस पॉइंट्स पर भी उपलब्धस है।

डीएचएल एक्स प्रेस इंडिया में सेल्स और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट संदीप जुनेजा ने कहा, 'दीपों का त्यौहार दिवाली परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाता है। महामारी ने त्यौहार मनाने के हमारे तरीके को बहुत प्रभावित किया है, लेकिन हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम वह खुशियाँ दें, जो दिवाली की प्रतीक हैं। यह ऑफर यह दिखाने का हमारा तरीका है कि हम वह टीम हैं, जो अपने ग्राहकों को उनके प्रियजनों के करीब लाने के लिये कड़ी मेहनत करती है। हम अपने महत्वह के प्रस्तोव के अनुसार अपने ग्राहकों को बेहतरीन दामों पर अबाध सेवाएं देना भी जारी रखना चाहते हैं।'

220 से ज्या।दा देशों और क्षेत्रों में फैले हमारे व्यापक वैश्विक नेटवर्क से हमारे ग्राहक विश्वा में कहीं भी अपने प्रियजनों को एक्सयप्रेस शिपमेंट्स भेज सकेंगे। इस ऑफर में? शिपमेंट की पूरी विजिबिलिटी है, जिसके लिये एसएमएस और ईमेल से प्रोएक्टिव अपडेट्स दिये जाते हैं, ताकि दुनियाभर में परेशानी से मुक्ती आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

डीएचएल - समूचे विश्व के लिए लॉजिस्टिक कंपनी

डीएचएल लॉजिस्टिक्स उद्योग का वैश्विक अग्रणी ब्राण्ड है। हमारा डीएचएल परिवार लॉजिस्टिक्स सेवाओं की विस्तृत सूची प्रस्तुत करता है, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पार्सल आपूर्ति, ई-कॉमर्स शिपिंग और निर्वाह समाधान, अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस, सड़क, वायु और समुद्री परिवहन तथा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन शामिल है। विश्व के 220 से अधिक देशों और क्षेत्रों में लगभग 400,000 कर्मचारियों के साथ डीएचएल लोगों और व्यवसायों को विश्वसनीयता से जोड़ते हुए वैश्विक व्यापार को सुगम बनाता है। तकनीक, जीवन विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा, ऊर्जा, ऑटोमोटिव और रिटेल जैसे वृद्धि करते बाजारों और उद्योगों के लिये विशेषीकृत समाधानों, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की प्रतिबद्धता और विकासशील बाजारों में मजबूत उपस्थिति के साथ डीएचएल ''समूचे विश्व के लिये लॉजिस्टिक्स कंपनी'' है।

डीएचएल ड्यूश पोस्ट डीएचएल समूह का हिस्सा है। वर्ष 2020 में इस समूह ने 66 बिलियन यूरो से अधिक राजस्व अर्जित किया था। स्थीयी कारोबारी प्रणालियों और समाज एवं पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्धता के साथ, ग्रुप दुनिया में सकारात्मथक योगदान करता है। ड्यूश पोस्ट डीएचएल समूह का लक्ष्यप 2050 तक जीरो-एमिशन लॉजिस्टिक्स प्राप्तर करना है।

विदेशी मुद्रा भंडार 1.2 अरब डॉलर घटकर 637.5 अरब डॉलर

मुंबई । एजेंसी

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 01 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 1.2 अरब डॉलर घटकर लगातार चौथे सप्ताह गिरते हुए 637.5 अरब डॉलर रह गया जबकि 99.7 करोड़ डॉलर कम होकर 638.64 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 01 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 1.3 अरब डॉलर कम होकर 575.5 अरब डॉलर रहा। इस दौरान स्वर्ण भंडार 12.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 37.56 अरब डॉलर पर रहा। वहीं, आलोच्य सप्ताह विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 13.8 करोड़ डॉलर घटकर 19.24 अरब डॉलर रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि 12.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.23 अरब डॉलर हो गया।

भारत में अंतिम सांसें गिन रहा कोरोना?

एक प्रतिशत से भी कम एक्टिव केस, जानें पूरा नंबर गेम

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में कोरोना संक्रमण के इलाजरत मरीज एक फीसदी से भी कम रह गए हैं। मंगलवार को 26,579 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद 2,14,900 रह गई। यह संख्या देश में कुल कोरोना मामलों के मुकाबले महज 0.63 फीसदी है। इसी के साथ संक्रमण से ठीक होने वालों की दर में सुधार हुआ है। अब रिकवरी दर 98.04 फीसदी पहुंच गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम अनुपात है। देश में इस वक्त जितने इलाजरत मरीज हैं, उनकी संख्या 212 दिनों में सबसे कम है। देश में मंगलवार को 14,313 नए संक्रमित मरीज मिले। जबकि पिछले 24 घंटे में इलाजरत मरीजों की संख्या में कुल 12,447 की कमी दर्ज की गई। देश में संक्रमण की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.48 फीसदी रह गई है, जो 190 दिनों में सबसे कम है। जबकि रोजाना पॉजिटिविटी रेट 1.21 फीसदी है, जो 43 दिनों में सबसे कम है।

सबसे कम सक्रिय मरीज वाले पांच राज्य

बिहार --- 36
राजस्थान --- 35
अंडमान निकोबार --- 10
दादरनगर हवेली --- 04
लक्ष्यद्वीप --- 03

सबसे ज्यादा इलाजरत मरीज वाले पांच राज्य

केरल ---1,02,012
महाराष्ट्र ---35,710
तमिलनाडु ---15,992
मिजोरम ---14,381
कर्नाटक --- 9,935

(स्रोत - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय)

देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा साढ़े चार लाख के पार

देश में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 4.50 लाख के पार हो गया है। इसके साथ ही भारत, दुनिया में कोरोना से हुईं सर्वाधिक मौतों के मामले में तीसरा सर्वाधिक प्रभावित देश बन गया है। इस सूची में सात लाख मौतों के साथ पहले नंबर पर अमेरिका और छह लाख मौतों के साथ दूसरे नंबर पर ब्राजील है।

मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को 2025-26 तक जारी रखने को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसका लक्ष्य स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के परिणामों को बनाए रखना एवं उनकी गति बढ़ाना है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । सरकारी बयान के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) के परिणामों पर जोर दिया जायेगा। साथ ही सभी शहरों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शुरू किया जायेगा । इसमें कहा गया है कि मिशन के तहत जनगणना 2011 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर जोर दिया जायेगा । इनमें ऐसे शहर हैं जिन्हें अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में शामिल नहीं किया गया था । बयान के अनुसार, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के वास्ते कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है । यह मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के स्वच्छता आयाम के तहत सभी सांविधिक शहरों को कम से कम खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस बनाना तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस बनाना है। इसमें अपशिष्ट जल का सुरक्षित तरीके के साथ शोधन हो और अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया जायेगा ।

मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि सभी शहरों को कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन हासिल हो। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किये गए स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 का मुख्य जोर अगले 5 साल में अब तक हासिल की गई स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के परिणामों को बनाए रखना व उनकी गति बढ़ाने पर होगा, ताकि मिशन के 'कचरा मुक्त' शहरी भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। मिशन के विभिन्न भागों का कार्यान्वयन एक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें आवश्यक आधारभूत ढांचे का विश्लेषण, 5 वर्षीय विस्तृत कार्य योजना और समयसीमा के साथ वार्षिक कार्य-योजनाएं शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि प्रत्येक शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा, साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) वाले शहरों और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में निर्माण और तोड़-फोड़ (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना की जायेगी । बयान के अनुसार, सभी पुराने कचरा स्थलों के जीर्णोद्धार पर जोर दिया जायेगा ताकि 15 करोड़ टन पुराने कचरे से ढकी 14,000 एकड़ भूमि को मुक्त किया जा सके।

बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई : जोशी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि ताप बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति मंगलवार को सामूहिक रूप से 20 लाख टन को पार कर गई है। उन्होंने दावा किया कि बिजलीघरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई है। देश के विभिन्न बिजली संयंत्र इस समय कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। जोशी ने बुधवार को ट्वीट किया, "मुझे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सभी स्रोतों से ताप बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति मंगलवार को 20 लाख टन से अधिक हो गई है। हम बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ा रहे हैं।" कोल इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिन के दौरान बिजली स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति पहले ही 16.2 लाख टन को पार कर गई है। वहीं कोयले का कुल उठाव 18.8 लाख टन हो गया है। जबकि इसका मासिक औसत 17.5 लाख टन है। इसके अलावा कोल इंडिया ने पिछले दो दिन के दौरान अपना उत्पादन भी बढ़ाकर 16 लाख टन किया है। कंपनी ने कहा है कि दशहरा के बाद उसका उत्पादन और बढ़ेगा, क्योंकि श्रमिक उस समय छुट्टियों के बाद काम पर लौटेंगे। इससे पहले जोशी ने मंगलवार को कहा था कि सरकार बिजली उत्पादकों की मांग को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा था कि कोयले की आपूर्ति को बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिदिन किया जाएगा, जो अभी 19.5 लाख टन है।

पीएम गति शक्ति योजना के प्रति सर्व-व्यापक दृष्टिकोण गेम चेंजर साबित होगा : फियो अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

फियो अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल ने मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लांच किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि यह न केवल विनिर्माण

बल्कि भारत से होने वाले निर्यातों के मामले में भी भारत की उत्पादक क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाएगी।

फियो अध्यक्ष ने कहा कि एक व्यापक संरचना के तहत सभी यूटिलिटी तथा अवसंरचना योजनाओं को लाया जाना अभूतपूर्व है। लंबे समय से, हमारे अवसंरचना क्षेत्र को अलग-अलग मंत्रालयों के कारण विलंबों, हितधारकों के विविध स्तरों तथा विभागीय देरी की संस्कृति का सामना करना पड़ता रहा है। इसकी वजह से अधिक समय लगता रहा है और लागत में वृद्धि होती रही है जिससे अवसंरचना केंद्रित विकास की गति प्रभावित होती रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक कनेक्टिविटी की पहुंच बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका लॉजिस्टिक्स लागत पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, हालांकि इसके लिए भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। डॉ. शक्तिवेल ने कहा कि एकीकृत योजना निर्माण तथा अवसंरचना कनेक्टिविटी के समेकित कार्यान्वयन के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर 16 मंत्रालयों को लाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह दृष्टिकोण है जिसे समान रूप से कई अन्य सेक्टरों पर भी लागू किया जा सकता है जहां अंतर-मंत्रालयी घनिष्ठ समन्वयन तथा निगरानी से अत्यधिक विकास हो सकता है। फियो अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार के मास्टर प्लान न केवल वैश्विक एफडीआई आकर्षित करेंगे बल्कि भारत को वैश्विक रूप से निवेश का सबसे पसंदीदा गंतव्य भी बनाएंगे।

किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देगा भारत

बिश्केक (किर्गिस्तान)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किर्गिस्तान के अपने समकक्ष रुस्लान कजाकबायेव के साथ द्विपक्षीय मुद्दों और अफगानिस्तान समेत कई अंतरराष्ट्रीय मामलों पर सोमवार को "सद्भावनापूर्ण एवं रचनात्मक" बातचीत की और इस दौरान भारत किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने पर सहमत हुआ। जयशंकर तीन मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से किर्गिस्तान, कजाखस्तान और आर्मेनिया की अपनी चार दिवसीय यात्रा के तहत रविवार को यहां पहुंचे।

जयशंकर ने ट्वीट किया, "किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रुस्लान कजाकबायेव के साथ सद्भावनापूर्ण और रचनात्मक बातचीत हुई। विकास परियोजनाओं में मदद करने के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा पर सहमति जताई। इसके अलावा अत्यधिक प्रभाव वाली सामुदायिक परियोजनाओं को लेकर आपसी सहमति बनी।"

उन्होंने कहा, "हमने भारतीय छात्रों की शीघ्र यात्रा और वीजा व्यवस्था में अधिक उदारता अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा की। हमने हमारे रक्षा सहयोग की सकारात्मक समीक्षा की।" इस बैठक के दौरान जयशंकर ने अफगानिस्तान में बदलते हालात पर भी चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट किया, "अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम को लेकर भारत और किर्गिस्तान का साझा दृष्टिकोण है।" जयशंकर ने बिश्केक में मानस-महात्मा गांधी पुस्तकालय को भारतीय महाकाव्य और उत्कृष्ट पुस्तकें भेंट कीं। बिश्केक में अपने प्रवास के दौरान जयशंकर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापरोव से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया था कि विदेश मंत्री के रूप में यह जयशंकर का किर्गिस्तान का पहला दौरा है। उसने यह भी बताया था कि इस यात्रा के दौरान कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि जयशंकर 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कजाखस्तान रहेंगे, जहां वे एशिया में संवाद एवं विश्वास निर्माण के उपाय (सीआईसीए) पर छठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जयशंकर 12 से 13 अक्टूबर तक आर्मेनिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह अपने आर्मेनियाई समकक्ष अरारत मिर्जोयान के साथ बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान से मुलाकात करेंगे। समझा जाता है कि तीन मध्य एशियाई देशों के नेताओं के साथ जयशंकर की बातचीत में अफगानिस्तान का घटनाक्रम प्रमुखता से उठ सकता है।

भारत का डब्ल्यूटीओ में बौद्धिक संपदा अधिकार से छूट देने, व्यापार अवरोध दूर करने का आह्वान

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैश्विक अभियान में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से छूट देने और नई व्यापार बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2020 में कोविड-19 संक्रमण के इलाज, उसकी रोकथाम के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों के लिये ट्रिप्स (व्यापार संबंधित पहलुओं पर बौद्धिक संपदा अधिकार) समझौते के कुछ प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव किया था। इस साल मई में इस संदर्भ में भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया समेत 62 सह-प्रायोजकों ने संशोधित प्रस्ताव दिये। ट्रिप्स समझौता जनवरी, 1995 में अमल में आया। यह कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट और अघोषित सूचना या व्यापार गोपनीयता के संरक्षण जैसे बौद्धिक संपदा पर बहुपक्षीय समझौता है।

गोयल ने इटली के नेपल्स में जी-20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में कहा, ''महामारी को देखते हुए जरूरी है कि हम आपूर्ति पक्ष की बाधाओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करके टीकों और अन्य कोविड-19 संबंधित स्वास्थ्य उत्पादों तक समान पहुंच सुनिश्चित करें। इसका एक तरीका ट्रिप्स छूट प्रस्ताव को स्वीकार करना है।'' उन्होंने टीके को लेकर भेदभाव या कोविड पासपोर्ट जैसे नयी व्यापार बाधाओं के समाधान पर भी जोर दिया। इससे आवाजाही बाधित होती हैं और महत्वपूर्ण सेवाएं देने के लिए आवश्यक कर्मियों का आना-जाना रुकता है।'' गोयल ने कहा,'कोविड-19 संकट ने हमें याद दिलाया है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। और इस तरह की अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति से निपटने के लिए एक समन्वित वैश्विक रणनीति की आवश्यकता है।'' उन्होंने यह भी कहा कि वस्तुओं की मुक्त आवाजाही के अलावा जी-20 देशों को स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच सुलभ कराने और लोगों के लिये उसे सस्ता बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। डब्ल्यूटीओ में मत्स्य क्षेत्र पर जारी बातचीत के बारे में गोयल ने कहा कि सुदूर समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने में लगे देशों को इस मामले में सब्सिडी बंद करनी चाहिए और खासकर अधिक मछली पकड़ने के संदर्भ में धीरे-धीरे अपनी क्षमता को कम करना चाहिए। उन्होंने गरीब और छोटे मछुआरों की आजीविका के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा चिंता दूर करने के साथ मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक रूप देने के लिये इस क्षेत्र में संतुलित रुख अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने जी-20 सदस्य देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये वित्तपोषण की अपनी प्रतिबद्धता पूरा करने का भी आग्रह किया। विकसित देश इस मामले में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में काफी पीछे हैं। जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में गोयल ने डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ब्राजील, चीन, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। कनाडा के मंत्री के साथ बैठक में उन्होंने नवनिर्वाचित सरकार के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के उपायों पर बातचीत की। उन्होंने दक्षिण कोरिया तथा यूरोपीय संघ के व्यापार मंत्रियों के साथ बैठकों में मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा में तेजी लाने को कहा।

कोरोना काल में नौकरियों में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना काल में वैसे तो नौकरियों पर संकट छाया रहा लेकिन उस दौरान जो भी नई नौकरियां उपलब्ध हुई, उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी है। विशेषज्ञ इसके पीछे कई कारण मानते हैं। जैसे वर्क फ्राम होम की सुविधा, नर्सों की अधिक नौकरियां निकलना और अपेक्षाकृत कम वेतन वाले स्टाफ को तरजीह दिया जाना।

केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है। ये आंकड़े सितंबर 2017 से जुलाई 2021 तक के हैं। इन आंकड़ों के गहन विश्लेषण से स्पष्ट नजर आता है कि कोरोना काल में ईपीएफओ से नए जुड़े अंशदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी पहले से बेहतर हुई है।

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 11040409 लोग ईपीएफओ के सदस्य बने। इनमें महिलाओं की संख्या 2520661 रही जो करीब 23 फीसदी बैठती है। कोरोनाकाल से पहले की तुलना में यह पांच फीसदी ज्यादा है। इसके बाद अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की नई भर्तियो में महिलाओं का प्रतिशत 23 के करीब रहा है। इस दौरान 8548819 भर्तियों में से 1945016 महिलाएं थी।

इस तरह बढ़ी भागीदारी

सितंबर 2017 से मार्च 2018 के बीच के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 8457404 नए अंशदाता ईपीएफओ से जुड़े जिनमें करीब 18 फीसदी यानी 1532496 महिलाएं थी। अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच 13944347 नए अंशदाता जुड़े जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 21 फीसदी के करीब थी। इस दौरान 2923962 महिलाएं ईपीएफओ की सदस्य बनीं। यह वह समय था जब कोरोना दस्तक दे चुका था और लाकडाउन शुरू हो चुका था।

कंपनियों को दिख रहा फायदे का सौदा

ईपीएफओ से जुड़े सूत्रों एवं बाजार के विशषज्ञों के अनुसार इसके पीछे तीन कारण प्रमुख हो सकते हैं। एक कोरोना काल में नर्सों की मांग सबसे ज्यादा रही इसलिए उनकी भर्तियां ज्यादा हुई। दूसरे, कंपनियों ने कम वेतन वाले स्टाफ को तरजीह दी हो सकती है, जिसमें महिलाओं को ज्यादा मौके मिले। तीसरे कोरोना के लंबे प्रभाव के चलते वर्क फ्राम होम का चलन बढ़ा है। कई महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के चलते या दूसरे शहर में जाने के कारण नौकरी नहीं करती हैं। लेकिन वर्क फ्राम होम ने उन्हें घर पर रहते हुए भी नौकरी के लिए आवेदन का मौका दिया और उन्हें नौकरियां मिलीं।

इस साल भी मिल रहे ज्यादा मौके

रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल, मई, जून और जुलाई के चार महीनों में भी नए जुड़ने वाले ईपीएफओ की महिला अंशधारकों में बढ़ोत्तरी कायम रही। अप्रैल में 775778 नए सदस्यों में 27.4 फीसदी यानी 212088 महिलाएं थी। जबकि मई में 628798 नये सदस्यों में 162189 यानी 25.8 फीसदी महिलाएं थीं। इसी प्रकार जून में 850896 नए सदस्यों में 197740 (23.4 फीसदी) महिलाएं हैं। जुलाई में 902209 नए सदस्यों में 215908 यानी 24 फीसदी महिलाएं शामिल हैं।

सितंबर में चीन का निर्यात 28 प्रतिशत बढ़कर 305.7 अरब डॉलर पर

बीजिंग। एजेंसी

चीन के निर्यात में सितंबर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, इस दौरान लौह अयस्क और अन्य जिंसों का आयात नरम पड़ा है, क्योंकि संपत्ति क्षेत्र में आई तेजी अब थम रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा ऊर्जा के उपयोग पर अंकुश भी लगाए गए हैं। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में चीन का निर्यात 28.1 प्रतिशत बढ़कर 305.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह अगस्त में निर्यात में दर्ज हुई 26 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। इसके अलावा यह अर्थशास्त्रियों के अनुमान से भी अधिक है। सितंबर में चीन का आयात 17.6 प्रतिशत बढ़कर 240 अरब डॉलर रहा। पिछले महीने आयात 33 प्रतिशत बढ़ा था। सीमा शुल्क एजेंसी के प्रवक्ता ली कुइवेन ने कहा, 'चीन का विदेश व्यापार का प्रदर्शन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अच्छा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी बढ़ी है।'' माह के दौरान चीन का वैश्विक स्तर पर व्यापार अधिशेष बढ़कर 68 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अगस्त में यह 52 अरब डॉलर रहा था। 2015 के बाद यह व्यापार अधिशेष का सबसे ऊंचा स्तर है। अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष सितंबर में बढ़कर 42 अरब डॉलर हो गया। अगस्त में यह करीब 38 अरब डॉलर था। समीक्षाधीन महीने में अमेरिका को चीन का निर्यात 30 प्रतिशत बढ़कर 57.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं अमेरिका से आयात 17 प्रतिशत बढ़कर 15.4 अरब डॉलर हो गया।

मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स में जागरूकता के लिये थ्री-आर थीम पर गरबा आयोजित

इंदौर (निप्र)। नवरात्रि के पावन अवसर पर अलवासा इंदौर स्थित मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स के प्रांगण में थ्री आर गरबे का आयोजन किया गया। यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में संस्था की मीडिया प्रभारी प्रो0 अर्पिता पटेल ने बताया कि इंदौर की स्वच्छता और थ्री-आर हेतु जागरूकता के निमित्त इस गरबे को थ्री आर थीम पर रखा गया। इंदौर स्वच्छता के ब्रांड एंबेसडर डॉ पुनीत द्विवेदी में बताया कि नवाचार जीवन का आधार है। क्रियेटिविटी और इन्नोवेशन के माध्यम से कचरे का रीसायकल -रीयूज कर कचरे को रेड्यूस किया जा सकता है। धीरे -धीरे कचरे को कम करना और समाप्त करने तक की हमारी तैयारी होनी चाहिये। मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा थ्री आर थीम पर गरबा किया गया। थ्री आर गरबा के विजेताओं को वेस्ट आईटम से बनाये गये बेस्ट गिफ्ट्स पुरस्कार स्वरूप दिये गये एवं उन्हें भी अपने घर एवं आस पास थ्री आर के क्रियान्वयन हेतु प्रयास करने के लिये जागरूक किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉ

अनिल खरया एवं उपाध्यक्ष श्री शांतनु खरया ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी एवं थ्री आर के प्रमोशन के और नये-नये तरीक़ों एवं एक्टिविटीज को करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में डॉ.सपना मालवीया (प्रभारी- फ़ार्मेसी कालेज), डॉ. नेहा शर्मा (प्रभारी प्रवेश), डॉ. कुलदीप अग्निहोत्र (प्रभारी - मैनेजमेंट) एवं श्री मती प्रद्नया कस्तूरे (प्रिंसिपल- मॉडर्न इंटरनैशनल स्कूल) आदि उपस्थित रहे।

15 अक्टूबर को है दशहरा, इस दिन करें ये काम, मां लक्ष्मी की होगी आसीम कृपा

दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत पर सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। दशहरा, हिंदूओं का प्रमुख त्यौहार है। हर वर्ष यह पर्व आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। पूरे देश में यह परंपरा है कि विजयादशी के दिन रावण के पुतले को फूंका जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा या विजया दशमी त्योहार का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। इस साल दशहरा 15 अक्टूबर को है। मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। विजया दशमी तिथि को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन विजय मुहूर्त में शुरु किया गया कोई भी कार्य लाभकारी होता है। दशहरा के दिन कुछ विशेष उपायों का भी महत्व है। जानिए इस दिन किन उपायों को करने से घर में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है-

1. दशहरा के दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से शत्रु पर विजय सुनिश्चित होती है।

2. विजया दशमी के दिन घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में रोली, कुमकुम या लाल रंग के फूलों से रंगोली या अष्टकमल की आकृति बनानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आगमन

होता है।

3. दशहरा के दिन शमी के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन पूजन में शमी के पत्ते अर्पित करने से आर्थिक लाभ होता है।

4. मान्यता है कि दशहरा के दिन पूजा घर में शमी के पेड़ की मिट्टी रखने से बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है।

5. दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलता है।

6.दशहरा के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से सफलता के मार्ग खुल जाते हैं।

7. मान्यता है कि दशहरा के दिन घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए रावण दहन की राख को सरसों के तेल में मिलाकर घर की हर दिशा में छिड़कना चाहिए।

8. दशहरा के दिन पान खाना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद होता है।

नोट– उपरोक्त दी गई जानकारी व सूचना सामान्य उद्देश्य के लिए दी गई है। हम इसकी सत्यता की जांच का दावा नही करतें हैं यह जानकारी विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, धर्मग्रंथों, पंचाग आदि से ली गई है । इस उपयोग करने वाले की स्वयं की जिम्मेंदारी होगी ।

दशहरे के दिन करते हैं ये 10 कार्य

शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद लोगों के विजय उत्सव मनाया था। इसी दिन श्रीराम ने रावण का वध किया था। आओ जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त और किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य।

दशमी तिथि : यह तिथि 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को शाम 06 बजकर 52 मिनट से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को शाम 06 बजकर 02 मिनट पर समाप्त होगी। अतः विजय दशमी का त्योहार 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा।

पूजा के मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 43 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक।

विजय मुहूर्त- दोपहर 2 बजकर 01 मिनट 53 सेकंड से दोपहर 2 बजकर 47 मिनट और 55 सेकंड तक।

अपराह्न मुहूर्त : 1 बजकर 15 मिनट 51 सेकंड से 3 बजकर 33 मिनट और 57 सेकंड तक तक।

अमृत काल मुहूर्त- शाम 6 बजकर 44 मिनट से रात 8 बजकर 27 मिनट तक।

दिन का चौघड़िया

लाभ – 07:53 एएम से 09:20 एएम तक
अमृत (वार वेला) – 09:20 एएम से 10:46 एएम तक
शुभ – 12:12 पीएम से 13:38 पीएम तक

रात का चौघड़िया

लाभ (काल रात्रि) – 21:05 पीएम से 22:39 पीएम तक
शुभ – 00:12 एएम से 01:46 एएम तक
अमृत – 01:46 एएम से 03:20 एएम तक

1. **दशहरे के के दिन रात में रावण दहन होता है।**
2. **इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा का खासा महत्व रहता है।**
3. **इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर और श्रीराम ने रावण का वध किया था।**
4. **इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा और उसके पत्तों के देने की परंपरा है।**
5. **इस दिन कोई नया कार्य करना, खरीददारी करना, नए वस्त्र पहनने का प्रचलन है।**
6. **इस दिन बच्चों को दशहरी दी जाती है अर्थात दशहरी के रूप में उन्हें इनाम, रुपये या मिठाई दी जाती है।**
7. **इस दिन परिवार और रिश्तों के सभी बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं।**
8. **इस दिन कई तरह के पकवान बनाकर गिलकी के भजिये तलकर खाने की परंपरा भी है।**
9. **इस दिन पटाखे भी छोड़े जाते हैं।**
10. **दशहरे के दिन आपसी शत्रुता भुलाकर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं।**

अमीर बनना चाहते हैं तो दशहरे पर कर लें नारियल का यह टोटका

सनातन धर्म में नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्रीफल यानी कि फलों में सर्वश्रेष्ठ फल. हर पूजा-पाठ, शुभ कार्य में नारियल का उपयोग होता है. बल्कि कोई नया काम शुरू करना हो या अहम यात्रा पर निकलना हो उसका श्रीगणेश नारियल फोड़कर ही किया जाता है। अमीर बनने में भी नारियल के टोटके बेहद कारगर हैं और इसके लिए दशहरे का दिन बहुत शुभ है।

घाटे को मुनाफे में बदल देगा ये टोटका

यदि बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा हो तो दशहरे के दिन सवा मीटर पीले कपड़े में एक नारियल लपेट लें। इस नारियल को जनेऊ और सवा पाव मिठाई के साथ किसी भी राम मंदिर में अर्पित कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में मुनाफा होने लगेगा।

वहीं परिवार की गरीबी दूर करने के लिए दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जटावाला नारियल, गुलाब, कमल के फूलों की माला,

सवा मीटर गुलाबी कपड़ा, सवा मीटर सफेद कपड़ा, सवा पाव चमेली, दही, सफेद मिठाई और एक जोड़ा जनेऊ माता को अर्पित करें। इसके बाद मां की कपूर और देसी घी से आरती उतारकर श्रीकनकधारा स्तोत्र का जाप करें। कुछ ही दिन में आर्थिक हालात बेहतर होने लगेंगे।

अमीर बने रहने का टोटका

दशहरे के दिन दीपावली की तरह चौकी सजाकर गणेश जी और महालक्ष्मी रखें। इसके बाद चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें। एक नारियल को साफ लाल कपड़े में लपेटकर कलश में रखें। इसके बाद दो बड़े दीपक लें। एक में घी का और दूसरे में तेल का दीपक जलाएं। एक दीपक को चौकी के दाहिनी ओर रख दें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में रख दें। वहीं एक छोटा दीपक गणेशजी के पास रखकर विधि-विधान से पूजा करें।

काम में सफलता पाने का टोटका

लंबे समय से रुका हुआ काम भी यह टोटका करने से पूरा हो जाता है। इसके लिए लाल सूती कपड़े में नारियल लपेट कर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करते समय नारियल से 7 बार अपनी मनोकामना कहें।

दशहरे पर राशि के अनुसार जपें श्रीराम का नाम

दशहरे के दिन अपनी-अपनी राशि अनुसार देवता का पूजन करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए जानें 12 राशियों के अनुसार इस दशहरे पर कैसे करें पूजन...

मेष राशि के जातक श्रीराम का पूजन करें, ॐ रामभद्राय नमः मंत्र का जाप करें।

वृषभ राशि के जातक हनुमानजी का पूजन करें, ॐ आञ्जनेयाय नमः मंत्र का जाप करें।

मिथुन राशि के जातक राम दरबार पर बेसन के लड्डू चढ़ाएं। ॐ रामचंद्राय नमः मंत्र का जाप करें।

कर्क राशि के जातक श्रीसीता-राम को मीठा पान चढ़ाएं। ॐ जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें।

सिंह राशि के जातक श्रीराम पूजन कर ॐ जनार्दनाय नमः मंत्र का जाप करें।

कन्या राशि के जातक हनुमान पूजन कर 'ॐ शर्वाय नमः' मंत्र का जाप करें।

तुला राशि के जातक राम दरबार पर शहद चढ़ाएं। ॐ सौमित्र वत्सल नमः मंत्र का जाप करें।

वृश्चिक राशि के जातक हनुमानजी पर चमेली का इत्र चढ़ाएं। भरत वंदितः नमः का जाप

करें।

धनु राशि के जातक तुलसी पत्र हाथ में लेकर ॐ दान्ताय नमः का जाप करें।

मकर राशि के जातक श्रीसीता-राम पर मौली चढ़ाएं। श्री रघुनंदन भरताग्रज नमः का जाप करें।

कुंभ राशि के जातक हनुमान मंत्र ॐ वायुपुत्राय नमः का जाप करें।

मीन राशि के जातक श्रीराम दरबार पर मेहंदी चढ़ाएं। दशरथ नंदनाय नमः का जाप करें।

दशहरे पर क्यों सजाते हैं गेंदे के फूल, जानिए राज

दशहरा पर्व विजय का प्रतीक है। इन दिनों मौसम खुश हो जाता है। पौधों पर बहार आ जाती है। गेंदे के फूल चारों तरफ मुस्कुराने लगते हैं। सवाल यह कि इस पर्व पर गेंदे के फूल क्यों सजाते हैं? वास्तव में ऐसा इसलिए है कि गेंदे इस मौसम में सहजता से उपलब्ध होते हैं और इसका धार्मिक महत्व भी है। गेंदे का रंग केसरिया है। यह रंग विजय, हर्ष और उल्लास का प्रतिनिधित्व करता है। इस फूल का धार्मिक महत्व भी अन्य फूलों से ज्यादा है। यूं तो गुलाब तथा चमेली के साथ और भी अन्य कई प्रकार के सुगंधित फूल धरती पर मौजूद हैं तब भी गेंदे के फूल का रंग शुभ का प्रतीक माना जाता है। इनके चटख रंग देखकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। केसरिया मिश्रित पीला या लाल मिश्रित पीला दोनों ही रंग पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं अतः प्रकृति प्रदत्त यह उपहार पर्व के प्रति स्नेह, सम्मान और प्रसन्नता दर्शाते हैं।

खाने के तेल की कमी से निपटने के लिए सरकार ने दीं कई रियायतें

हैरान करने वाले रेकॉर्ड लेवल पर पहुंचा आयात!

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत में पाम तेल का रिकॉर्ड आयात होने से खाद्य तेल आयात सितंबर के दौरान 63 प्रतिशत के उछाल के साथ रिकॉर्ड 16.98 लाख टन हो गया। खाद्य तेल क्षेत्र के प्रमुख संगठन एसईए ने यह जानकारी दी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने एक बयान में कहा कि वनस्पति तेलों का कुल आयात, जिसमें खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार के तेल शामिल हैं, सितंबर के दौरान 66 प्रतिशत बढ़कर 17,62,338 टन हो गया, जबकि सितंबर, 2020 में यह आयात 10,61,944 टन का हुआ था।

एसईए ने कहा, ''सितंबर, 2021 के दौरान खाद्य तेलों के आयात ने किसी एक महीने में 16.98 लाख टन के आयात का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अक्टूबर 2015 में भारत ने 16.51 लाख टन का आयात किया था।'' एसईए के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता ने कहा, ''वर्ष 1996 में भारत द्वारा पाम तेल का आयात शुरू करने के बाद से सितंबर, 2021 में 12.62 लाख टन पाम तेल का आयात किसी एक महीने में सबसे अधिक आयात को दर्शाता है।''

अखाद्य तेलों का आयात सितंबर में बढ़कर 63,608 टन हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 17,702 टन था। नवंबर, 2020 से सितंबर, 2021 (11 महीने) के दौरान, वनस्पति तेलों का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,22,57,837 टन की तुलना में दो प्रतिशत बढ़कर 1,24,70,784 टन हो गया। कुल वनस्पति तेल आयात में से खाद्य तेल का आयात 1,19,50,501 टन से बढ़कर 1,20,85,247 टन हो गया। अखाद्य तेल का आयात 3,07,333 टन से बढ़कर 3,85,537 टन हो गया। वनस्पति तेल विपणन वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक चलता है।

आयात शुल्क में रियायत से बढ़ा आयात

एसईए ने कहा कि एक जुलाई, 2021 से आरबीडी पामोलिन के आयात के लिए नीति में छूट के कारण अगस्त और सितंबर, 2021 के दौरान आयात में तेजी से वृद्धि हुई। नवंबर, 2020 से सितंबर, 2021 तक कुल मिलाकर आयात 50 प्रतिशत से अधिक उछलकर 6.28 लाख हो गया। एसोसिएशन ने कहा कि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 4.16 लाख टन आरबीडी पामोलिन का आयात हुआ था।

आरबीडी पामोलिन और आरबीडी पाम तेल का आयात, जुलाई, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक के लिए 'प्रतिबंधित' से 'मुक्त' श्रेणी में हो गया है। एसोसिएशन ने कहा, ''पिछले कुछ महीनों में देश में खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की नीति में लगातार बदलाव किए गए हैं।''

कितना लगता है आयात शुल्क?

मौजूदा समय में कच्चे पाम तेल पर प्रभावी आयात शुल्क 24.75 प्रतिशत है, जबकि रिफाइंड पामोलीन और रिफाइंड पाम तेल पर शुल्क 35.75 प्रतिशत है। कच्चे सोयाबीन और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर यह शुल्क क्रमशः 24.75 प्रतिशत और 35.75 प्रतिशत है। इसी तरह कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 24.75 प्रतिशत और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 35.75 प्रतिशत का शुल्क प्रभावी है। कच्चे रैपसीड तेल पर प्रभावी शुल्क 38.50 प्रतिशत और परिष्कृत रैपसीड तेल पर 49.50 प्रतिशत है। इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को आरबीडी पामोलिन और कच्चे पाम तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं। देश मुख्य रूप से अर्जेंटीना से कच्चे सोयाबीन के तेल का आयात करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष दोहरे अंक की वृद्धि हासिल करने के करीब: सीतारमण

बोस्टन। एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष दोहरे अंक की वृद्धि हासिल करने की तरफ बढ़ रही है और यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगले साल आर्थिक वृद्धि 7.5 से 8.5 प्रतिशत के बीच होगी जो अगले दशक तक कायम रहेगी। सीतारमण ने मंगलवार को यहां हार्वर्ड केनेडी स्कूल में बातचीत के दौरान कहा, 'जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने के सवाल है तो हम इस वर्ष इसमें दो अंकों की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में होगा। वही अगले वर्ष में सालाना आधार पर यह वृद्धि निश्चित तौर पर आठ प्रतिशत के आस पास रहेगी।' उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अभी तक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बारे में कोई आकलन नहीं किया है लेकिन विश्व बैंक, आईएमएफ और अन्य रेटिंग एजेंसियों ने भारत के लिए करीब-करीब इस तरह की वृद्धि की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री ने कहा, 'अगले साल भी भारतीय अर्तव्यवस्था कहीं न कहीं आठ से नौ प्रतिशत या 7.5 से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि अगले एक दशक तक यही वृद्धि कायम रहेगी और इससे कम होने का कोई कारण भी नहीं दिखता।'

डीबीटी ने 'लॉकडाउन' के दौरान सरकार को त्वरित प्रभावी उपाय करने में मदद की: रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम ने 2020 में अप्रत्याशित रूप से कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये लगाये गये 'लॉकडाउन' के दौरान सरकार को त्वरित प्रभावी उपाय करने में मदद की है। हालांकि योजना के व्यापक दायरे के बावजूद कुछ खामियां बरकरार हैं। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। लेखक वी अनंत नागेश्वरन, लवीश भंडारी और सुमिता काले ने 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: स्थिति और आगे की चुनौतियां' शीर्षक वाली रिपोर्ट में आगे कहा कि भारत का डीबीटी कार्यक्रम 2013 से आगे बढ़ रहा है। नागेश्वरन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 'पिछले कुछ वर्षों से जारी डीबीटी के परिणामस्वरूप 2020 में अप्रत्याशित कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान त्वरित प्रभावी कदम उठाए गए। डीबीटी के जरिये लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में काफी मदद मिली है। उसके बावजूद कुछ खामियां हैं।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि एक उचित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की जरूरत है। इसका समन्वय प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग के स्तर पर होने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में, कुल 179.9 करोड़ लाभार्थियों को सहायता मिली।

छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी में छूट के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित

इंदौर (निप्र)। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री शरद अग्रवाल एवं इंदौर महानगर मीडिया प्रभारी संतोष वाधवानी ने भाजपा की मोदी सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को व्यापारियों को जीएसटी के संबंध में दी गई छूट के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में किसी पिछले कानून में रजिस्टर्ड होने के कारण सरकार ने सभी को उएऊ नंबर लेना अनिवार्य किया था। पिछले कानून में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, लेकिन अब चूंकि किसी व्यापारी या प्रोफेशनल का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है और व्यापारी की कोई इंटरस्टेट बिक्री भी नहीं है साथ ही उसने उएऊ में माइग्रेशन जरूरी होने के कारण करा लिया था। यदि अब उन्हें महसूस होता है की उएऊ के दायरे में वह नहीं आता है तो सरकार ने पहले उएऊ लगने के दिन से 30 दिन में ऊिं-29 फॉर्म भरकर व्यापारी को अपना उएऊ नबर निरस्त करवाने की सुविधा दी थी। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री शरद अग्रवाल एवं संतोष वाधवानी ने कहा है कि यह एक अच्छी सुविधा है क्योंकि कई छोटे छोटे व्यापारी जैसे रिटेल किराना वाले, पान वाले, स्टेशनरी वाले, चाय-पोहे वाले और चूंकि 20 लाख की लिमिट में प्रोफेशनल एवं सर्विस सेक्टर वाले भी आते हैं। इन सभी को अभी ही इस बारे में शांति से निर्णय कर लेना चाहिए कि उएऊ नंबर की हमें आवश्यकता है या नहीं। क्योंकि एक बार नंबर परमानेंट हो जाने के बाद आप नंबर कैंसल कराने का निर्णय लेते हैं तो जब जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उस पर टैक्स देना (वर्तमान दर से) पड़ेगा। मतलब ऐसा माना जाएगा कि आप नंबर कैंसल करा रहे हैं तो आपने ये पूरा माल स्वयं टैक्स भरकर खरीद लिया।

बागवानों को झटका: एग्रो वेस्ट पेपर पर छह फीसदी बढ़ा जीएसटी, सेब कार्टन और होगा महंगा

नई दिल्ली। एजेंसी

हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के आखिर में बागवानों को एक और झटका लगा है। एक अक्तूबर से कार्टन में इस्तेमाल होने वाले एग्रो वेस्ट पेपर पर लगने वाले जीएसटी को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। एग्रो वेस्ट पेपर पर छह प्रतिशत जीएसटी बढ़ाया गया है। जीएसटी बढ़ने से अगले साल बागवानों को कार्टन और भी महंगा मिलेगा। इससे बागवानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सीजन के आरंभ में प्रदेश सरकार ने बागवानों को आश्वासन दिया था कि कार्टन व सेब पैकिंग ट्रे के मूल्यों पर किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसके बावजूद 10 रुपये से अधिक महंगा कार्टन बिका। सेब खरीद करने वाली कंपनियों ने बागवानों को सेब का मूल्य बेहद कम दिया।

इससे बागवानों को नुकसान उठाना पड़ा। अब एग्रो वेस्ट पर जीएसटी बढ़ने से एक फिर बागवानों पर ही मार पड़ी है। कुल्लू फलोत्पादक मंडल के अध्यक्ष प्रेम शर्मा ने कहा कि सरकार कृषि और बागवानी में प्रयोग होने वाली सामग्री पर लगातार टैक्स बढ़ा रही है। इससे बागवानों को फलों और सब्जियों के उत्पादन पर काफी अधिक खर्चा आ रहा है। लेकिन जब किसान और बागवान अपनी उपज को बाजार में बेचने जाते हैं, तो उन्हें कई बार लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। सरकार किसानों, बागवानों की अनदेखी कर रही है। कार्टन में प्रयोग होने वाले एग्रो वेस्ट पेपर पर लगने वाले टैक्स में वृद्धि की मार बागवानों पर पड़ेगी। इसलिए बागवानों के हित में इस वृद्धि को जल्द वापस लिया जाए।

IIP: उद्योगों ने दी अच्छी खबर, अगस्त में उत्पादन 12% बढ़ा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के औद्योगिक उत्पादन (IIP) में अगस्त में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। अगस्त 2021 में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में खनन क्षेत्र का उत्पादन 23.6 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र का 16 प्रतिशत बढ़ा। अगस्त 2020 में औद्योगिक उत्पादन 7.1 प्रतिशत घटा था। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह अप्रैल-अगस्त में आईआईपी (Index of Industrial Production) में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में आईआईपी में 25 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले साल मार्च से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। उस समय इसमें 18.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी। अप्रैल 2020 में लॉकडाउन की वजह से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होने से औद्योगिक उत्पादन 57.3 प्रतिशत घटा था।

खुदरा महंगाई के मोर्चे पर भी आई अच्छी खबर

खाद्य वस्तुओं के दाम कम होने से खुदरा महंगाई सितंबर महीने में घटकर 4.35 प्रतिशत पर आ गई। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई अगस्त 2021 में 5.30 प्रतिशत और सितंबर 2020 में 7.27 प्रतिशत थी।

बंद होंगे सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाले कारखाने

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वेबिनार सम्पन्न

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने एवं प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 तथा नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार में क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर / देवास के अंतर्गत आने वाले जिलों इन्दौर, खरगौन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर देवास तथा शाजापुर की समस्त नगर निगम, नगर पालिकाओं / नगर परिषदों के अधिकारियों, प्लास्टिक उद्योगों, शहरों के प्लास्टिक व्यावसायियों, टॉफी उद्योग, होटल / मैरिज गार्डन के प्रतिनिधियों नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों, शासकीय अधिकारियों, एन.जी.ओ. शिक्षण संस्थान तथा बोर्ड के संबंधित अधिकारियों सहित लगभग 151 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आर. के. गुप्ता द्वारा स्वागत भाषण देते हुये बताया गया कि केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात प्लास्टिक की वस्तु जिसको डिस्पोज या रिसायकल से पहले एक काम के लिये एक ही बार इस्तेमाल किया जाना है को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 01 जुलाई 2022 से प्रभावशील होंगे। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें 17 प्रकार के उत्पाद जैसे प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बडस, बैलून के साथ उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक एवं सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल का सामान, प्लेटस, कप्स, ग्लास, फोर्क, स्पून, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे आदि कटलरी आईटम, मिठाई के डिब्बो के चारो और लपेटने वाली फिल्म, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट की पैंकिंग में उपयोग होने वाली प्लास्टिक तथा 100 माइक्रॉन से कम मोटाई के बेनर्स एवं स्टिकर शामिल हैं, के निर्माण एवं क्रय-विक्रय तथा उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त वेबीनार का प्रमुख उद्देश्य संबंधित प्लास्टिक उद्योगो के प्रतिनिधियों, नियमों के क्रियान्वयन हेतु दायित्वाधीन नगरीय निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम संशोधित 2021 की

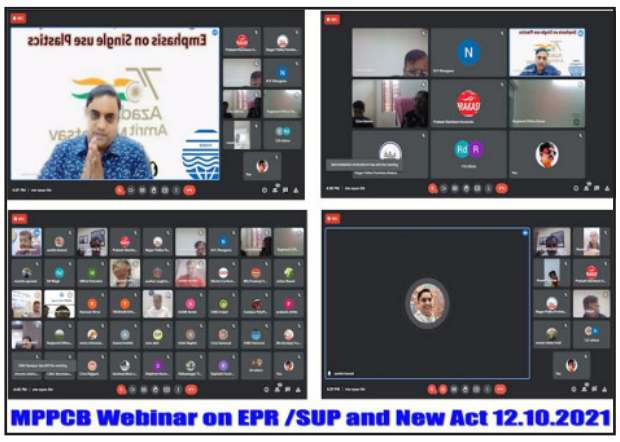

जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया।

तकनीकी सत्र में प्रथम प्रजेन्टेशन अधीक्षण यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल डॉ. एम. एल. पटेल द्वारा 'सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध एवं इसके विकल्प' विषय पर दिया गया। कार्यक्रम में रिसाईक्लिंग कर बनाये जा रहे विभिन्न उत्पादों की जानकारी अध्यक्ष इंडियन प्लास्टिक फोरम श्री सचिन बंसल एवं शक्ति प्लास्टिक के श्री राहुल पोतदार द्वारा उनके व्याख्यान के माध्यम से प्रतिभागियों को दी गई। संचालक इको प्रो इंवायरमेन्टल सर्विसेज श्री अजय जैन द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठो के प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध तकनीकों के संबंध में जानकारी दी गई। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री अनूप चतुर्वेदी ने दी।

क्षेत्रीय अधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि म.प्र. राज्य में पॉलीथीन कैरीबैग पर पूर्ण प्रतिबंध गत 24 मई 2017 से लागू हैं, आगे इसके साथ सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी प्रतिबंध आगामी 01 जुलाई 2022 से लागू हो जायेंगे। उपरोक्तानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का उद्योगों में निर्माण बंद कराने का दायित्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का होगा। इसके क्रय-विक्रय तथा इस्तेमाल पर प्रतिबंध के पालन कराने की जिम्मेदारी नगरीय निकायो एवं पंचायतो को दी गई है। उक्त संशोधन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्पादन करने वाली इकाईयों के उपर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की होगी एव क्रय-विक्रय उपयोग इत्यादि पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के अधिकार नगरीय निकायों एवं पंचायतों को सौपे गये हैं। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक आईटम जैसे पेपर के कप, पेपर ग्लास, पत्तों से बने दोने, मिट्टी से बने कुल्हड़, सुराही, लकड़ी से बने कटलरी आईटम एवं स्टिक्स इत्यादि का उपयोग किया जावें। इसी प्रकार पूजा पंडाल में शादियों में प्लास्टिक से बने सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल के उपयोग को हतोत्साहित करना श्रेयस्कर होगा। बताया गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम में 'एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर रिसपांसबिलिटी' का प्रावधान किया गया है। म.प्र. राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 लागू हैं एवं इसके तहत नगर की सीमा में उत्पन्न होने वाले सूखे एवं गीले घरेलू अपशिष्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन, परिवहन, उपचार एवं निपटान की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई है। समस्त नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों से नियमों का पालन करने का आवाहन किया गया।

विशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित नगरीय विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री राजीव निगम द्वारा वेबीनार को संबोधित करते हुए सभी नगरीय निकायों, व्यापारियों, उद्यमियों से अनुरोध किया गया कि वे केन्द्र एवं राज्य शासन के नियमों का पालन उनके क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से करें ताकि किसी को भी किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना न करना पड़े। उन्होने नगरीय निकायों की ओर से आश्वस्त किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध नगरीय सीमा में सभी सी.एम.ओ. द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया जायेगा। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन श्री सुनील व्यास द्वारा किया गया।

औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 11.9 प्रतिशत बढ़ा, मुद्रास्फीति सितंबर में पांच माह के निम्न स्तर पर

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है। जहां औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में अगस्त में 11.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई, वहीं खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में कम होकर पांच महीने के निम्न स्तर 4.35 प्रतिशत पर आ गयी। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन सुधरा है और यह महामारी-पूर्व के अगस्त, 2019 के स्तर को पार कर गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निम्न तुलनात्मक आधार तथा विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इन क्षेत्रों का उत्पादन कोविड-पूर्व स्तर को पार कर गया है।

औद्योगिक उत्पादन में 77.63 प्रतिशत भारांश रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत रही। इस दौरान खनन क्षेत्र का उत्पादन 23.6 प्रतिशत तथा बिजली क्षेत्र का 16 प्रतिशत बढ़ा। अगस्त, 2020 में औद्योगिक उत्पादन 7.1 प्रतिशत घटा था। आंकड़े के अनुसार अगस्त, 2021 में आईआईपी 131.1 अंक रहा, जो पिछले साल समान महीने में 117.2 अंक रहा था। अगस्त, 2019 में यह 126.2 अंक था। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह अप्रैल-अगस्त में आईआईपी में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में आईआईपी में 25 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले साल मार्च से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। उस समय इसमें 18.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी। निवेश का संकेतक माने जाने वाले पूंजीगत सामान क्षेत्र का उत्पादन अगस्त, 2021 में 19.9 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले समान महीने में यह 14.4 प्रतिशत घटा था। अगस्त, 2021 में टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़ा जबकि अगस्त, 2020 में यह 10.2 प्रतिशत घटा था। इसी तरह गैर-टिकाऊ सामान क्षेत्र का उत्पादन 5.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले समान महीने में इसमें तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी। दूसरी तरफ, सब्जी और अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम कम होने से खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर पांच महीने के निम्न स्तर 4.35 प्रतिशत पर आ गयी मुद्रास्फीति अगस्त में 5.3 प्रतिशत तथा सितंबर, 2020 में 7.27 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर इस साल सितंबर में नरम होकर 0.68 प्रतिशत रही। यह पिछले महीने 3.11 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है।

सब्जी की महंगाई दर में सितंबर में 22.47 प्रतिशत की कमी आयी जबकि अगस्त में इसमें 11.68 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। फल, अंडा, मांस और मछली तथा दाल एवं उत्पादों के मामले में कीमत वृद्धि की दर नरम रही। हालांकि, ईंधन और प्रकाश के मामले में मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 13.63 प्रतिशत हो गयी जो अगस्त में 12.95 प्रतिशत थी।

इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि अगस्त में 5.3 प्रतिशत के मुकाबले सितंबर, 2021 में खुदरा महंगाई दर के कम होकर 4.35 प्रतिशत पर आना उल्लेखनीय है और यह इक्रा के अनुमान से बेहतर है। मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं के दाम कम होने से महंगाई दर कम हुई है। इसके अलावा आवास क्षेत्र का भी कुछ योगदान है। आईडीएफसी एएमसी में कोष प्रबंधक और अर्थशास्त्री श्रीजीत बालासुब्रमण्यम ने कहा कि मुद्रास्फीति में गिरावट का प्रमुख कारण खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में नरमी है। हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति 5.8 प्रतिशत पर बनी हुई है। आरबीआई ने 2021-22 के लिये सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

भारत को 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए 5630 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता की जरूरतः रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत को 2070 तक शून्य उत्सर्जन वाला देश बनने के लिए अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 5630 गीगावॉट करनी होगी। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस समय भारत में 100 गीगावॉट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से सौर क्षमता 40 गीगावॉट है। सरकार ने 2030 तक अपनी कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता को 450 गीगावॉट तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत को सोलर फोटो वोल्टिक (पीवी) कचरे के निपटान के लिए भी अपेक्षित रिसाइकिलिंग क्षमता विकसित करनी होगी। सीईईडब्ल्यू के अध्ययन में यह भी बताया गया है कि 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए बिजली उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग में कटौती करनी होगी और 2040 से 2060 के बीच इसमें 99 प्रतिशत तक कमी लाने की जरूरत होगी। इसके अलावा कच्चे तेल की खपत में 2050 से 2070 के बीच 90 प्रतिशत तक कमी लाने की जरूरत होगी। अध्ययन में कहा गया कि ग्रीन हाइड्रोजन औद्योगिक क्षेत्र की कुल ऊर्जा जरूरतों का 19 प्रतिशत पूरा कर सकता है। ऐसे में इस बदलाव में हाइड्रोजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। अध्ययन में यह भी कहा गया कि सीसीएस तकनीक में कोई बड़ी सफलता और कम लागत वाले वित्त की व्यवस्था, इस बदलाव की आर्थिक लागत को घटाने में मदद कर सकती है। सीईईडब्ल्यू के फेलो डॉ. वैभव चतुर्वेदी ने कहा, ''भारत जैसे विशाल और विविधता वाले विकासशील देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की शुरुआत करने के वर्ष और शून्य उत्सर्जन वर्ष के बीच कम से कम 30 वर्ष का अंतर रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को नई ऊर्जा व्यवस्था के लिए योजना बनाने और उसे अपनाने के लिए पर्याप्त समय देते हुए बाधारहित बदलाव को सुनिश्चित करेगा।''

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।